हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ

(तिथि 18 जनवरी 2026, समय 1810 (10 मिनट)

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज असम के नागांव जिले के कलियाबोर से दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी दिखाई ।

- कामाख्या-रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस से हरियाणा को कामाख्या के साथ बेहतर कनेक्टिविटी मिली ।
- नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया ।
- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है विकसित भारत - जी राम जी योजना प्रधानमंत्री की देश के हर श्रमिक को काम के साथ सम्मान, समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका के अधिकार की गारंटी है।

- मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जी राम जी योजना पर लोगों को भ्रमित कर रही है ।
- वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गरैप के चौथे चरण की पाबंदियां लागू की गई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज असम के नागांव जिले के कलियाबोर में छह हजार 950 करोड़ रुपये से अधिक की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी । प्रधानमंत्री ने आज असम के नागांव जिले में कलियाबोर से दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी भी दिखाई। ये रेलगाड़ियां - कामाख्या-रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़-लखनऊ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस हैं। कामाख्या-रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस से हरियाणा से कामाख्या जाने वाले तीर्थ यात्रियों को लाभ होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा -

---

नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पिछले वर्ष दिसंबर में इंडिगो की बड़े पैमाने पर उड़ानों में देरी और उन्हें रद्द करने के मामले में लगाया गया है।

हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंडिगो के परिचालन में व्यवधान के कारणों की व्यापक समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए महानिदेशालय द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति द्वारा की गई विस्तृत जांच के बाद यह जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माने में नागर

विमानन के कई नियमों के उल्लंघन के लिए एक करोड़ 80 लाख रुपये का एकमुश्त प्रणालीगत जुर्माना और पिछले वर्ष पांच दिसंबर से आगामी 10 फरवरी तक 68 दिनों के लिए 30 लाख रुपये का दैनिक जुर्माना शामिल है।

महानिदेशालय द्वारा गठित जांच समिति ने कहा कि व्यवधान के मुख्य कारण परिचालन का अत्यधिक अनुकूलन, अपर्याप्त नियामक तैयारी, प्रबंधन संरचना और परिचालन नियंत्रण में कमियां थीं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि विकसित भारत - जी राम जी योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की देश के हर श्रमिक को काम के साथ-साथ सम्मान, समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका के अधिकार की गारंटी है।

श्री नायब सिंह सैनी आज पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में विकसित भारत - जी राम जी पर राज्य स्तरीय सम्मेलन में उपस्थित श्रमिकों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना मेहनतकश श्रमिकों के जीवन स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए एक मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है, उसे गांवों और श्रमिकों के विकास के बिना पूरा नहीं किया सकता।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनरेगा की विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025' को देश के सामने रखा। इसे विकसित भारत- जी राम जी कानून कहा जा रहा है। यह केवल मनरेगा का नाम बदलना नहीं है, बल्कि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का संपूर्ण आधुनिकीकरण है। उन्होंने कहा कि इस नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। यही नहीं, नए कानून में राज्यों को फसल बुवाई और कटाई के समय 60 दिन के लिए काम रोकने का अधिकार भी दिया गया है। इससे श्रमिकों को इन 60 दिनों का काम तो मिलेगा ही, विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत भी 125 दिन का काम मिलेगा। इससे पूरे भारत वर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7 हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में हर श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये अधिक मिलेंगे। हरियाणा में प्रतिदिन देश में सर्वाधिक 400 रुपये की दर से न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। इससे हर श्रमिक की वार्षिक आय कम से कम 50 हजार रुपये हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वी.बी. जी-राम-जी योजना में अब 15 दिन की जगह साप्ताहिक वेतन भुगतान की व्यवस्था की गई है, ताकि मजदूर को समय पर उसका पैसा मिल सके। उन्होंने काँग्रेस द्वारा मनरेगा की जगह विकसित भारत -जी राम जी नाम का विरोध किए जाने पर कहा-

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है और जी राम जी योजना पर लोगों को भ्रमित करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब में मनरेगा के तहत श्रमिकों के भुगतान में भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी पंजाब सरकार दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही।मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे कांग्रेस के दुष्प्रचार से भ्रमित ना हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्रमिकों, गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से आए योजना के श्रमिकों से संवाद किया और जी राम जी योजना के संबंध में उनके अनुभव भी लिए। योजना की एक लाभार्थी ने आकाशवाणी से बातचीत में योजना को बीओमेट्रिक हजरी से जोड़ने की प्रशंसा की।

वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए फरीदबाद सहित पूरे दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी गरैप के चौथे चरण की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।फरीदाबाद के उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यह पाबंदियां लागू की हैं।उन्होंने कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। प्रतिबंधों में सभी निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध शामिल है, जिसमें मिट्टी का काम, पाइलिंग, खाई खोदना, और सड़क निर्माण गतिविधियां और बड़ी मरम्मत शामिल हैं।

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण किया जा रहा है। भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

वे पलवल अनाज मंडी में नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अभिनंदन जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है।

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के 11 वर्षों में लोगों को बदलता हुआ भारत देखने को मिल रहा है।